उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकृष्ट करने के लिए 'इन्वेस्ट यूपी' में समर्पित कंट्री डेस्क किए स्थापित

इन तीन कंट्री डेस्क में शामिल हैं: अमेरिका+, यूरोप+ और जापान+

लखनऊ, 21 जुलाई 2024: मुख्य सचिव-सह-अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त के निर्देशानुसार 'इन्वेस्ट यूपी' (उ.प्र. सरकार की निवेश प्रोत्साहन एजेंसी) के अंतर्गत तीन समर्पित कंट्री डेस्क स्थापित किए गए हैं, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने में सहायक होंगे। ये हैल्पडेस्क इस प्रकार तैयार किए गए हैं, जिनसे विभिन्न देशों की कंपनियों को निवेश प्रक्रिया के बारे में समझना एवं निवेश करना सुगम हो सके।

उल्लेखनीय है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ डी आई) आकर्षित करने तथा फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक समर्पित एफडीआई, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 एवं फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति-2023 की घोषणा की है। इस नीति का लक्ष्य बड़ी वैश्विक कंपनियों के लिए उत्तर प्रदेश को निवेश के पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। 'इन्वेस्ट यूपी' राज्य की प्रमुख निवेश प्रोत्साहन एजेंसी है और इसको इस नीति के कार्यान्वयन एवं प्रोत्साहन के लिए नोडल एजेंसी नामित किया गया है।

उक्त कंट्री डेस्क इसलिए स्थापित किए गए हैं ताकि प्रदेश में निवेश की इच्छुक कंपनियों को पूर्ण सुगमता प्रदान की जा सके। इन डेस्क में शामिल हैं:- **अमेरिका प्लस डेस्क (संयुक्त राज्य अमेरिका-यूएसए और कैनेडा), जिसके कंट्री लीड प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, श्री अनिल कुमार सागर** हैं; **यूरोप प्लस डेस्क (यूके, नीदरलैंड्स, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन व स्विटज़रलैंड)** जिसके **कंट्री लीड सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी - इन्वेस्ट यूपी**, श्री अभिषेक प्रकाश; तथा **जापान प्लस (जापान व दक्षिण कोरिया) के कंट्री लीड अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी - इन्वेस्ट यूपी** हैं।

कंट्री डेस्क के मुख्य कार्य
प्रारंभ से अंत तक निवेश-प्रक्रिया एवं उसके बाद भी सहायता के लिए उपलब्ध रहना
उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के अवसरों, निवेशों के बारे में जानकारी प्रदान करना
परियोजना स्थलों की पहचान करने एवं भूमि अधिग्रहण में में कंपनियों की सहायता करना
सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (पी पी पी) को प्रोत्साहित करना
निवेशकों को समयबद्ध तरीके से स्वीकृतियाँ, अनुमोदन प्राप्त करने में सहायता करना
सरकारी अधिकारियों के साथ संवाद को सुविधाजनक बनाना

साथ ही तीनों कंट्री डेस्क्स के कार्य में सहयोग करने के लिए **उद्यमी मित्रों, समन्वय अधिकारियों एवं परामर्शियों** को भी नियुक्त किया गया है।

प्रत्येक कंट्री डेस्क की जिम्मेदारी निवेश प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक जानकारी देना तथा निवेश प्रक्रिया को आसान बनाना होगा। कंट्री डेस्क्स, **कंट्री लीड्स** की देखरेख में निवेशकों से संवाद व संपर्क करेंगे एवं राज्य की नीतियों के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे।

समन्वय अधिकारी निवेशकों को आवश्यक जानकारी प्रदान करने के साथ, दैनिक कार्ययोजना का भलीभांति अनुपालन करेंगे, तथा निवेश प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी हितधारकों के साथ बातचीत का दौर जारी रखेंगे।

परामर्शी एवं उद्यमी मित्र निवेशकों को उचित परामर्श प्रदान करेंगे, जोखिम को कम करने एवं सही रणनीति बनाने में उनकी सहायता करेंगे।

मुख्य सचिव, श्री मनोज कुमार सिंह ने उत्तर प्रदेश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन में राज्य की एफडीआई नीति के महत्व पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा "कंट्री डेस्क्स की स्थापना राज्य के माहौल को निवेशक-अनुकूल बनाने की दिशा में हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हमारा उद्देश्य विशेषज्ञों की सहायता से राज्य में विदेशी निवेश को और बढ़ाना है, जो उत्तर प्रदेश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास को गति देगा एवं राज्य को और अधिक समृद्ध बनाएगा"।

इन्वेस्ट यूपी की एक विशेष पहल के रूप में कंट्री डेस्क्स की स्थापना वैश्विक निवेशकों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने और राज्य में निवेश परियोजनाएं स्थापित करने के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। यह प्रयास उत्तर प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा तथा राज्य को अंतरराष्ट्रीय निवेश के एक प्रमुख केंद्र के रूप में पहचान दिलाएगा।